



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2004/कार्तिक 4, 1926

No. 248]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/KARTIKA 4, 1926

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2004

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों बिछाने के लिए अनुपूरक दिशानिर्देश

फा. सं. पी-20012/5/99-पीपी/ओआर-2.— भारत सरकार, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों बिछाने के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 - खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना फा0 सं0 पी-20012/5/99-पीपी के क्रम में दिनांक 20.11.2002 के उपर्युक्त दिशानिर्देशों की श्रेणी 1(iii) के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइनों के लिए निम्नलिखित अनुपूरक दिशानिर्देश लोक हित में जारी करती है।

कामन कैरियर क्षमता

1. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों बिछाने के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना फा0 सं0 पी-20012/5/99-पीपी के पैरा 3.4 के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली 'कामन कैरियर' क्षमता, पाइपलाइन की पूरी अवधि के दौरान स्वामी/प्रस्तावक के अलावा किसी अन्य पक्षकार को प्रथम उपयोग का अधिकार प्रदान करती है।

2. यदि क्षमता, कामन कैरियर क्षमता में से उपलब्ध हो तो स्वामी/प्रस्तावक इस विनिर्देश के साथ इसका उपयोग कर सकता है कि अगर कोई अन्य पक्षकार कामन कैरियर क्षमता के माध्यम से परिवहन मांगता है तो स्वामी/प्रस्तावक खाली कर देंगे और नामोद्विष्ट स्तर तक तुरन्त कामन कैरियर क्षमता उपलब्ध कराएंगे।

पाइपलाइन की पूर्णता के लिए समयावधि

3. पाइपलाइन परियोजना को संस्वीकृति/अनुमोदन पत्र में उल्लिखित समयावधि में चालू करना आवश्यक होगा जिसमें संस्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 महीने की बाहरी सीमा होगी।

बैंक गारंटी

4. स्वामी/प्रस्तावक को अनुमोदित निर्धारित समय के अनुसार पाइपलाइन परियोजना चालू करने के लिए गारंटी के रूप में परियोजना परिव्यय के 2% के बराबर राशि या प्रस्तावित पाइपलाइन के 2 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी संस्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 महीनों के बाद किसी भी समय भुनाए जाने योग्य होगी और केवल सरकार के परामर्श पर उन्मोचन योग्य होगी। यदि परियोजना की पूर्णता में परियोजना की संस्वीकृति/अनुमोदन की तारीख से 36 महीने से अधिक का विलंब हो जाता है, तो बैंक गारंटी का आश्रय लिया जा सकता है।

5. प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन (आरओयू) बैंक गारंटी के निष्पादन और इसे सरकार के पास जमा कराने के बाद आरंभ किया जाएगा।

6. बैंक गारंटी संस्वीकृति पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर जमा करा दी जाए अन्यथा संस्वीकृति रद्द मानी जाएगी।

7. बैंक गारंटी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पाइपलाइन के चालू होने पर और संस्वीकृति/अनुमोदन पत्र के जरिए लगाई गई शर्तों के संतोषजनक अनुपालन होने पर मुक्त किया जाएगा।

आरओयू का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

8. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए केवल सेवारत सरकारी अधिकारियों पर ही विचार किया जाएगा।

स्वामित्व का हस्तांतरण

9. जहां कोई पाइपलाइन कार्यान्वयनकारी कंपनी एक सहायक कंपनी हो और इसे इसकी धारक/मूल कंपनी के तुलन पत्र के आधार पर संस्वीकृति/अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया हो वहां अनुमति ऐसी पाइपलाइन कार्यान्वयनकारी सहायक कंपनी में प्रबंधन/अधिकांश धारिता में किसी परिवर्तन से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्राप्त करनी होगी।

किसी पाइपलाइन परियोजना में क्षमता प्राप्तकर्ताओं की पात्रता

10. किसी ऐसी पाइपलाइन परियोजना में क्षमता प्राप्त करने के लिए कोई भी पक्षकार प्रस्तावक से संपर्क कर सकता है जिसके लिए दिनांक 20.11.2002 की पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिसूचना फा0सं0 पी-20012/5/99-पीपी के दिशानिर्देशों के तहत ईओआई जारी की जा चुकी है। क्षमता प्राप्त करने वाले पक्षकारों की पात्रता इन आधार पर सीमित नहीं की जाएगी कि क्षमता प्राप्त करने वाला पक्षकार न तो कोई रिफाइनरी है और न ही उसके पास कोई विपणन अधिकार हैं।

विविध

11. ये पूरक दिशानिर्देश 20.11.2002 के पूर्व के दिशानिर्देशों के संदर्भ में पढ़े जाएं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिशानिर्देशों/पूरक दिशानिर्देशों के सहज कार्यान्वयन के लिए स्पष्टीकरण अथवा निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

प्रभ दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2004

Supplementary Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines

F. No. P-20012/5/99-PP/OR-II.— In continuation of notification F.No.P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002 of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas published in the Gazette of India Extraordinary, Part I – Section I, regarding Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines, the Government of India are pleased to issue, in public interest, the following supplementary guidelines for pipelines falling under category 1 (iii) of the aforesaid guidelines 20.11.2002.

Common Carrier Capacity

1. The “common carrier” capacity to be built under para 3.4 of the Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines notification F.No.P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002 provides the right of first use to any party other than the owner/proposer, throughout the life of the pipeline.
2. In the event that capacity is available out of the common carrier capacity, the owner/proposer may utilise the same with the stipulation that should any other party seek transportation through common carrier capacity, the owner/proposer would vacate and make available common carrier capacity up to the designated level immediately.

Time Frame For Completion of Pipeline

3. Pipeline project will be required to be commissioned within the time period provided in the sanction/approval letter, which shall have an outer limit of 36 months from the date of sanction/approval.

Bank Guarantee

4. The owner/proposer will be required to furnish an irrevocable bank guarantee of an amount equivalent to 2% of the project outlay or Rs.2 lakhs per kilometer of pipeline proposed, whichever is higher, as a guarantee for commissioning the pipeline project as per the approved time schedule. The irrevocable bank guarantee shall be encashable any time after 36 months from the date of the sanction/approval and will be dischargeable only on advice of the Government. If the completion of the project is delayed beyond 36 months from the date of sanction/approval of the project, then the bank guarantee may be invoked.
5. The ROU acquisition would be commenced after execution of Bank Guarantee and its deposit with the Government.
6. The Bank Guarantee may be deposited within 30 days of issue of sanction letter failing which sanction letter would stand withdrawn.
7. The bank guarantee will be discharged on commissioning of the pipeline within the time period specified and satisfactory compliance of conditions imposed through the sanction/approval letter.

Competent Authority for Acquiring ROU

8. Only serving Government Officers will be considered for working as Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962.

Transfer of Ownership

9. Where a pipeline implementing company is a subsidiary company and has been granted sanction/approval letter on the basis of its holding/parent company's balance sheet, permission of Ministry of Petroleum and Natural Gas will be required to be obtained prior to any change in management/majority holding in such pipeline implementing subsidiary.

Eligibility of Players Seeking Capacity in a Pipeline Project

10. Any party may approach the proposer to seek capacity in a pipeline project for which an EOI has been issued under Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines notification F. No. P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002. Eligibility of parties seeking capacity will not be limited on the grounds that the party, seeking capacity is neither a refinery nor possessing any marketing rights.

Miscellaneous

11. These supplementary guidelines may be read in the context of the earlier guidelines of 20.11.2002. Ministry of Petroleum and Natural Gas shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the Guidelines /Supplementary Guidelines

PRABH DAS, Jt. Secy.

3218 G2/04-2